

न्यायमूर्ति ए. एल. बहरी और न्यायमूर्ति एस. एस. ग्रेवाल के समक्ष

आयकर अधिकारी, फरीदाबाद- आवेदक।

बनाम

किशन लाल कथूरिया, -प्रतिवादी.

आपराधिक अपील सं. 1983 का 309-डीबीए

15 मई, 1991।

आयकर अधिनियम, 1961 - धारा 277 - आयकर रिटर्न में कथित रूप से गलत विवरण देना - आयकर विभाग द्वारा लगाया गया जुर्माना- करदाता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए आधार के रूप में ली गई आय की जब्ती- अपील में न्यायाधिकरण ने छिपाने के तत्व को गायब पाया और जुर्माना रद्द कर दिया- इस तरह के निष्कर्ष- आपराधिक कार्यवाही पर प्रभाव -दोषसिद्धि को रद्द किया जा सकता है।

माना जाता है कि अधिकारियों के आदेश, जो अंततः निर्धारिती के पक्ष में हैं, आपराधिक न्यायालय द्वारा विचार के लिए प्रासंगिक हैं। यदि छिपाने का तत्व गायब है, जैसा कि ट्रिब्यूनल द्वारा कहा गया है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी को पता था कि रिटर्न और सत्यापन में बयान गलत था या ऐसा माना जाता था। ऐसी परिस्थितियों में, सत्र न्यायाधीश द्वारा यह सही कहा गया था कि केवल यह दिखाकर कि रिटर्न फर्न में त्रुटि थी या झूठी गवाही दी गई थी, अभियुक्त की दोषसिद्धि को बनाए नहीं रखा जा सकता है। कुछ और होना

चाहिए कि इस तरह की त्रुटि या चूक अभियुक्त की जानकारी या विश्वास के लिए झूठी थी जो धारा 277 के तहत नहीं की गई थी।

(पैरा 4)

फरीदाबाद के सत्र न्यायाधीश श्री सुरिंदर सरूप की अदालत के दिनांक 4 नवम्बर, 1982 के आदेश के खिलाफ अपील में श्री एलएन मित्तल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी फरीदाबादके 4 अगस्त, 1981 के आदेश को निरस्त करते हुए अभियुक्तों को बरी करने का आदेश दिया गया था ।

आरोप: आयकर अधिनियम 1961 की धारा 211 के तहत।

आदेश: बरी करना।

आपराधिक मामला सं. 1978 की धारा 128-ए/3/1981 की 165/3, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 211 के तहत शिकायत।

अपील के आधार पर यह प्रार्थना की गई है कि अपील को स्वीकार किया जाए, और सत्र न्यायाधीश के फैसले को रद्द कर दिया जाए और आरोपी प्रतिवादी को उपयुक्त रूप से दंडित किया जाए।

अपीलकर्ता की ओर से एके मित्तल, अधिवक्ता।

उत्तरदाता के लिए नेमो

निर्णय

ए. एल. बहरी, न्यायमूर्ति

(1) कृष्ण लाई कथूरिया पर आयकर अधिनियम की धारा 277 के तहत मुकदमा चलाया गया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, फरीदाबाद ने 4 अगस्त, 1981 को उन्हें दोषी ठहराया और 3 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना का भुगतान करने में विफल रहने पर उन्हें छह महीने के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। इस आदेश को फरीदाबाद के सत्र न्यायाधीश के समक्ष सफलतापूर्वक चुनौती दी गई, जिन्होंने 4 नवंबर, 1982 के अपने आदेश के तहत दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया। यह अपील आयकर अधिकारी की है।

(2) इस अधिनियम की धारा 277 के तहत कृष्ण लाई कथूरिया के खिलाफ आयकर अधिकारी द्वारा आपराधिक शिकायत दर्ज की गई थी। आरोपी कृष्ण लाई कथूरिया मेसर्स इंडियन कास्टिंग, फरीदाबाद के नाम और शैली के तहत कच्चा लोहा बनाने का कारोबार कर रहा था। कृष्ण लाई प्रोपराइटर हैं। उन्होंने आकलन वर्ष 1972-73, लेखा वर्ष 1971-72 के लिए 29 जुलाई, 1972 को आयकर रिटर्न दाखिल किया था। रिटर्न के साथ, बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाता, विविध लेनदारों और डेबिट कर्ताओं की सूची प्रस्तुत की गई थी। रिटर्न की पुष्टि के कृष्ण लाई ने की थी। आयकर अधिकारी ने करदाता को निर्देश दिया कि वह क्लोजिंग स्टॉक की प्रतियां और बैंक से प्रमाण पत्र दाखिल करें, जिसमें गिरवी रखे गए स्टॉक का विवरण और कुछ अन्य दस्तावेज हों। 30 अक्टूबर, 1974 को ये दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे। 31 मार्च, 1972 को 12,000 रुपये मूल्य के 22 टन पिग आयरन और 960 रुपये मूल्य के 2 टन कास्ट आयरन स्क्रेप और

525 रुपये मूल्य के उपभोग्य स्टोर यानी 12,485 रुपये मूल्य के सामान को स्टॉक में दिखाया गया था। आयकर अधिकारी ने बैंक से कुछ रिकॉर्ड भी हासिल किए। इसमें विसंगतियां थीं और करदाता को नोटिस देने के बाद उसने अघोषित आय के रूप में करदाता की आय में 12,000 रुपये जोड़ दिए। मूल्यांकन आदेश 31 दिसंबर, 1974 को किया गया था। सहायक अपीलीय आयुक्त ने 28 जनवरी, 1976 को करदाता की अपील खारिज कर दी थी और दूसरी अपील 17 नवंबर, 1976 को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा खारिज कर दी गई थी। इसके बाद, आयकर अधिकारी ने 12,000 रुपये की उपरोक्त आय को छिपाने के लिए जुर्माना कार्यवाही शुरू की और 30 मार्च, 1977 के आदेश के अनुसार, आयकर अधिकारी ने 12,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जिसमें कहा गया कि करदाता ने रिटर्न के सत्यापन में गलत बयान दिया था। यह गलत था और करदाता जानता था कि यह गलत है। आयकर अधिनियम की धारा 277 के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज करके कार्यवाही शुरू की गई।

(3) शिकायतकर्ता ने पीडब्ल्यू 1, वीआर ऋषि, आयकर अधिकारी, पीडब्ल्यू 2, एलआर ढींगरा, सहायक निदेशक, पीडब्ल्यू 3, मिस अनीता, क्लर्क, आयकर अधिकारी के कार्यालय से और पीडब्ल्यू 4, भारतीय स्टेट बैंक में सहायक श्री एमएल गारी से पूछताछ की। आरोपी ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान देते हुए फर्म का मालिक होने की बात स्वीकार की और रिटर्न दाखिल किया। हालांकि, उन्होंने इस बात से इनकार किया कि आयकर अधिकारी ने सीधे बैंक से कोई छूट मांगी थी। उन्होंने आगे कहा कि आयकर अधिकारी द्वारा लगाए गए 12,000 रुपये के जुर्माने को अंततः आयकर अपीलीय

न्यायाधिकरण ने अपील में रद्द कर दिया था। उन्होंने झूठे आरोप लगाए। बचाव में उन्होंने पांच गवाह पेश किए।

(4) अपीलकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता श्री ए. के. मित्तल ने तर्क दिया है कि ट्रिब्यूनल के आदेश परमुख्य रूप से निर्णय के आधार पर दोषसिद्धि के आदेश को रद्द करने के लिए विद्वान न्यायाधीश का दृष्टिकोण, जिसके तहत 12,000 रुपये के जुर्माने को रद्द कर दिया गया था, कानून में गलत है। वकील के अनुसार, आपराधिक अदालत आयकर अधिनियम के तहत अधिकारियों के फैसले से बाध्य नहीं थी और आपराधिक मामले में एक स्वतंत्र निर्णय लेने की आवश्यकता थी। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले में पेश किए गए सबूतों का हवाला देने के बाद सही निष्कर्ष निकाला था कि आयकर रिटर्न का सत्यापन गलत था और यह आरोपी की जानकारी में था। इससे पहले कि मैं इस विषय पर उद्धृत अधिकारियों के साथ-साथ सत्र न्यायाधीश द्वारा भरोसा किए गए अधिकारियों का उल्लेख करूं, अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश का उल्लेख करना आवश्यक होगा, जिसके तहत 12,000 रुपये के जुर्माने को एक पक्ष रखा गया था, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या ट्रिब्यूनल द्वारा कोई निष्कर्ष दर्ज किया गया था। क्या यह छिपाने का मामला था या नहीं। यदि यह छिपाने का मामला था, तो यह बताया जा सकता है कि आरोपी को यह भी बताया जा सकता है कि रिटर्न में दी गई जानकारी और झूठी प्रविष्टियों के बारे में इसका सत्यापन उसकी जानकारी में था। आयकर अधिनियम की धारा 277 निम्नानुसार है: –

"277. यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत या उसके तहत बनाए गए किसी नियम के तहत किसी सत्यापन में बयान देता है, या एक

खाता या बयान देता है जो गलत है, और जिसे वह या तो जानता है या गलत मानता है, या सच नहीं मानता है, तो वह दंडनीय होगा:

- (i) ऐसे मामले में जहां कर की राशि, जो विवरण या खाते को सत्य मानने पर चोरी की गई होती, एक लाख रुपये से अधिक है, एक अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा होगी जो छह महीने से कम नहीं होगी लेकिन जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है:
- (ii) किसी अन्य मामले में, एक अवधि के लिए कठोर कारावास के साथ जो तीन महीने से कम नहीं होगा, लेकिन जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना लगाया जा सकता है।

पूर्वोक्त प्रावधान दो बातों पर विचार करता है। सबसे पहले, कि किसी व्यक्ति ने किसी भी सत्यापन या किसी भी खाते में अपने बयान में गलत दावा किया था और दूसरा यह कि वह जानता था या विश्वास करता था कि वही गलत था, या उसने इसे सच नहीं माना। इन अवयवों के प्रमाण पर यह कहा जा सकता है कि उसने अपराध किया था और उसे दंडित किया जा सकता है जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है। डीए ट्रिब्यूनल का आदेश है। ऑपरेटिव भाग निम्नानुसार है: -

दोनों पक्षों को सुनने के बाद मेरा मानना है कि तथ्यों के आधार पर जुर्माना देना उचित नहीं है। अपीलीय सहायक आयुक्त ने स्टॉक बुक में विसंगतियां पाई, जैसा कि एस्सी द्वारा उल्लेख किया गया है और स्टॉक की धारणा का स्पष्टीकरण न देने के लिए बैंक को दिए गए आंकड़े, आयकर अधिकारी ने कुछ बिक्री का अनुमान लगाया।

दुर्भाग्यपूर्ण है कि करदाता दूसरी अपील के चरण में भी विफल रहा। लेकिन मेरे सामने एकमात्र सवाल यह है कि क्या इस तरह की पुष्टि अपने आप में स्पष्ट रूप से छिपाना स्थापित करती है या नहीं। मेरा विचार है कि ऐसा नहीं है। जुर्माने को न्यायोचित ठहराने के लिए आयकर अधिकारियों को यह साबित करना होगा कि उन्होंने अपने आदेशों में जो कुछ किया है, उससे कहीं अधिक कुछ और किया गया है और यह कि करदाता की ओर से स्पष्ट रूप से छिपाया जा रहा है। इसलिए, करदाता का मामला पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के 76 आईटीआर 693 और 83 आईटीआर 369 में उनके लॉर्डशिप के फैसलों के अनुपात में आता है।

उपरोक्त आदेश के अवलोकन से कोई संदेह नहीं रह जाता है कि ट्रिब्यूनल द्वारा एक विशिष्ट निष्कर्ष दर्ज किया गया था कि यह छिपाने का मामला नहीं था और उस स्कोर पर 12,000 रुपये का जुर्माना रद्द कर दिया गया था। अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने अपने तर्क के समर्थन में सी.जी. बालाकृष्णन और अन्य बनाम आयकर अधिकारी (1) में केरल उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया है कि अधिनियम की धारा 277 के तहत कार्यवाही स्वतंत्र है और सिर्फ इसलिए कि मूल्यांकन-कार्यवाहियां रद्द कर दिए गए थे तो दोषसिद्धि को रद्द करने का कोई आधार नहीं था।

फैसले को पढ़ने से पता चलता है कि पी. जयप्पन बनाम एस. के. पेरुमल (2) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया गया था और निम्नलिखित अंश को उद्धृत किया गया था:

अदालत ने कहा, 'आपराधिक मामले में आरोपी की दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए अपराध के सभी तत्वों को स्थापित करना होता है. इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपराधिक न्यायालय को अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के परिणाम पर उचित सम्मान देना होगा - जो मुद्दे पर संबंधित है और एक मामले में वह अधिनियम के तहत पारित आदेश के आलोक में कार्यवाही को छोड़ सकता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि आयकर अधिनियम के तहत कार्यवाही का परिणाम आपराधिक अदालत के लिए बाध्यकारी होगा। आपराधिक अदालत को उसके समक्ष पेश किए गए सबूतों के आधार पर स्वतंत्र रूप से मामले का फैसला करना होगा।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि जयपरके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हालांकि अधिनियम की धारा 277 के तहत आपराधिक मामले में कार्यवाही स्वतंत्र थी, हालांकि, किसी दिए गए मामले में अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के आधार पर उन कार्यवाही को हटाया जा सकता है। आगे *परकुश चरेड* बनाम *आयकर अधिकारी* (3) में इस अदालत के फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है। यह माना गया कि ट्रिब्यूनल के निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि

याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था और कोई गलत खाता दायर नहीं किया गया था, निर्धारिती के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी नहीं रह सकती थी और रद्द करने योग्य थी। *उत्तम चंद बनाम आयकर अधिकारी (4)* मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अनुपात अलग-अलग था। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निम्नानुसार कहा गया था :-

पीठ ने कहा, 'आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज इस निष्कर्ष के मद्देनजर कि रिकॉर्ड पर मौजूद पूरी सामग्री के मूल्यांकन से यह स्पष्ट है कि रानी में फ्रिमति जान एक वास्तविक कंपनी थी और यह कि फर्म एक वास्तविक कंपनी थी, हम यह नहीं देखते कि गलत रिटर्न दाखिल करने के लिए करदाता पर कैसे मुकदमा चलाया जा सकता है। तदनुसार, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और अभियोजन को रद्द करते हैं।'

संत प्रकाश बनाम आयकर आयुक्त मामले में न्यायमूर्ति हरबंस सिंह राय के फैसले का हवाला दिया गया है इस मामले में, मजिस्ट्रेट ने आरोपी को तलब किया है और उसके बाद, आयकर अधिनियम के तहत अधिकारियों ने आकलन कार्यवाही को रद्द कर दिया था। यह माना गया कि शिकायत अभी भी आगे बढ़ सकती है और अभियोजन को रद्द नहीं किया जा सकता है। यह कहा जा सकता है कि निर्णय का अनुपात, हाथ में लिए गए मामले पर लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि अभियोजन पक्ष को प्रारंभिक चरण में रद्द करने की आवश्यकता नहीं थी। आरोपी पहले ही मुकदमा चला चुका है और मुकदमा

पूरा हो चुका है। अब प्रश्न यह है कि अधिकरण के आदेश के साथ यदि कोई मूल्य जोड़ा जा सकता है तो उसे क्या मूल्य दिया जा सकता है। इस मामले पर आगे एस. एस. कांग, जे. इन *डी. एन. भसीन और एक अन्य बनाम भारत संघ* (6) में विचार किया गया। आपराधिक कार्रवाई शुरू होने के बाद आयोग अपीली ने आय में जोड़े गए अंशों को हटा दिया और करदाता द्वारा दाखिल मूल रिटर्न को स्वीकार कर लिया। यह माना गया था कि उस आधार पर आपराधिक कार्यवाही रद्द की जा सकती है। *टीजेटम, चंद और पी. जयप्पन के मामले* में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया था। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था:-

उन्होंने कहा, 'अगर आयुक्त (अपील) इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि करदाताओं की आय में की गई बढ़ोतरी उचित नहीं है और उसे हटाने का आदेश दिया तो यह दलील नहीं दी जा सकती कि करदाताओं ने कर चोरी की कोशिश की या अपने रिटर्न के सत्यापन में गलत बयान दिए। गलत रिटर्न दाखिल करने या कर चोरी का प्रयास करने के लिए आपराधिक अदालत में करदाताओं पर मुकदमा चलाने का कोई मामला नहीं बचा था। आपराधिक शिकायतों को रद्द किया जाना चाहिए।

फैसले के अनुपात से दर्शाई गई कानून की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि अधिकारियों के आदेश, जो अंततः करदाता के पक्ष में हैं, आपराधिक अदालत

द्वारा विचार के लिए प्रासंगिक हैं। यदि छिपाने का तत्व गायब है, जैसा कि ट्रिब्यूनल द्वारा कहा गया है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी रिटर्न और सत्यापन में बयान को गलत मानते हैं या ऐसा होने का दावा करते हैं। अपीलकर्ता के वकील की इस दलील में कोई दम नहीं है कि छिपाने के तथ्य का झूठी गवाही या ऐसा मानने से कोई लेना-देना नहीं है। इस तरह के परित्यक्त रुख में, सत्र न्यायाधीश के लिए यह आवश्यक नहीं था कि वह उसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पेश किए गए सबूतों पर विस्तार से विचार करें। सत्र न्यायाधीश द्वारा यह सही कहा गया था कि केवल यह दिखाकर कि प्रस्तुत किए गए रिटर्न में त्रुटि थी या गलत कथन था,

अभियुक्त की दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। कुछ और होना चाहिए कि इस तरह की त्रुटि या चूक आरोपी की जानकारी या विश्वास के लिए झूठी थी। इसमें कोई संदेह नहीं है, दूसरे घटक को किसी विशेष मामले में परिस्थितियों के दिए गए सेट से निष्कर्ष निकालकर साबित किया जाना है और कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं हो सकता है जैसा कि अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया है। हालांकि, वर्तमान मामले में जब ट्रिब्यूनल द्वारा इस तरह के निष्कर्ष को आदेश में दर्ज किया गया है, जिसे वर्तमान आपराधिक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान पारित किया गया था, तो इस निष्कर्ष पर पहुंचने में प्रासंगिक होने के कारण इसे सही ढंग से ध्यान में रखा गया था कि धारा 277 का दूसरा घटक नहीं बनाया गया था। अपील में कोई दम नहीं पाए जाने पर इसे खारिज किया जाता है।

आर. एन. आर.

न्यायमूर्ति ए. एल. बहरी और न्यायमूर्ति एस. एस. ग्रेवाल से पहले

पंजाब राज्य - अपीलकर्ता,

बनाम

भजन सिंह - प्रतिवादी।

1983 की आपराधिक अपील संख्या 212-डीबीए।

29 मई, 1991।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 - खंड 7, 16 (1) (क) (i) और

(ii) - दूध का नमूना- विभिन्न प्रयोगशालाओं में विश्लेषण- अलग-अलग रिपोर्ट - निदेशक की रिपोर्ट। केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला लोक विश्लेषक का स्थान लेती है।

यह माना जाता है कि जब दूध के नमूनों का विश्लेषण पहले सार्वजनिक विश्लेषक द्वारा और फिर निदेशक, केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला द्वारा किया गया है, तो बाद की रिपोर्ट सामग्री का अंतिम और निर्णायक प्रमाण है। ये रिपोर्ट लोक विश्लेषक की रिपोर्टों का स्थान लेती हैं। चूंकि निदेशक ने पाया था कि दूध के नमूनों में वसा नहीं है, इसलिए नमूनों को मिलावटी माना जाता है और इन मामलों में दोनों आरोपियों को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा 16 (1) (ए) (आई) के साथ धारा 7 के तहत अपराध करने का दोषी ठहराया जाता है।

(पैरा 4)

श्री आरएल आनंद, पीसीएस, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कपूरथला की अदालत का आदेश 17 नवंबर, 1983 को जारी किया गया है।

आरोपियों को बरी कर दिया।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सिद्धांत रॉयल
प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
जगाधरी, हरियाणा